योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

10 दसवीं
पंचवर्षीय योजना
2002 - 2007

खण्ड - III

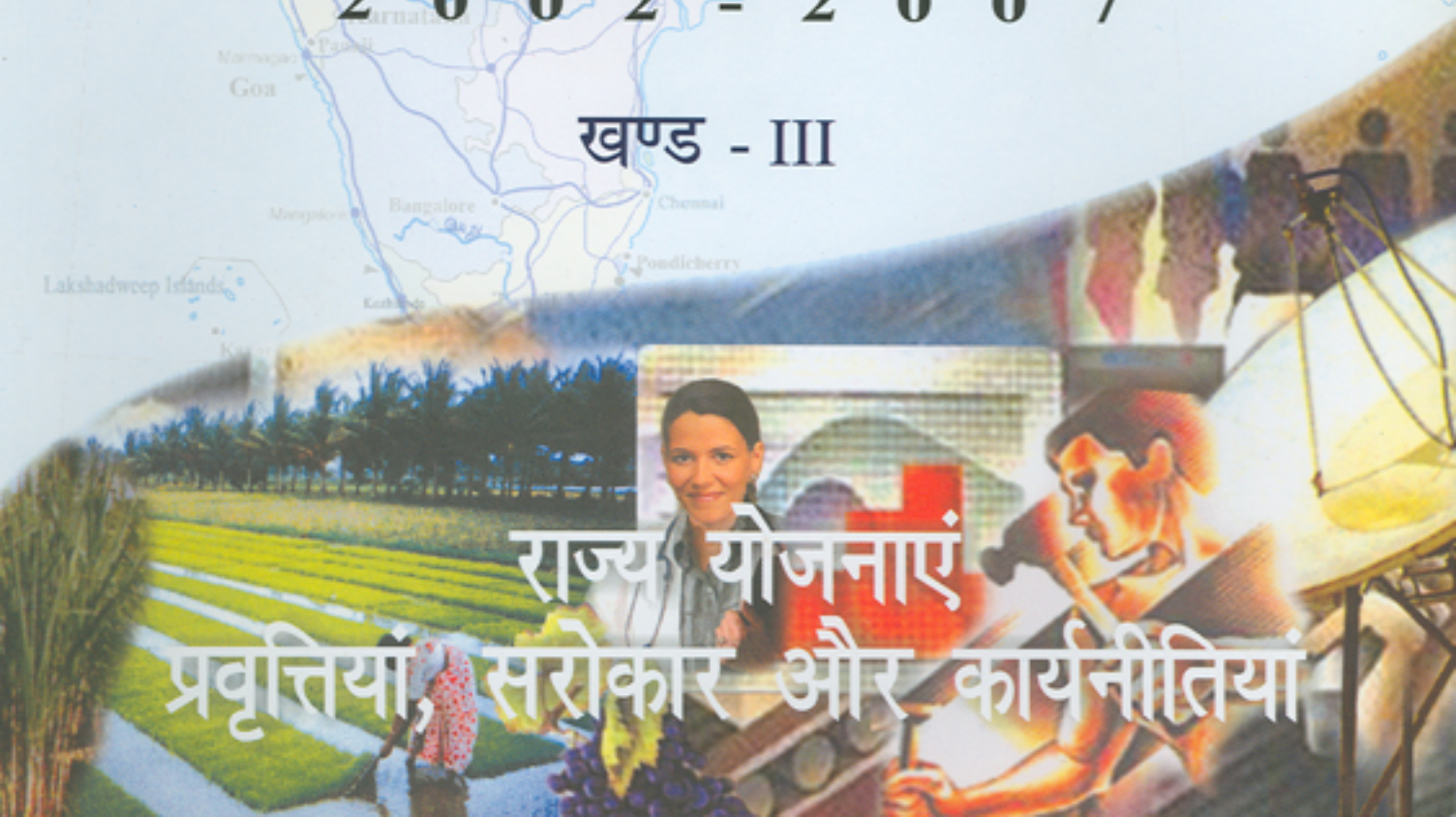

राज्य योजनाएं
प्रवृत्तियां, सरोकार और कार्यनीतियां

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के एक भाग के रूप में पहली मरतबा राज्य योजनाओं से संबंधित एक अलग खंड शामिल किया जा रहा है। विगत् में योजना आयोग इन समस्याओं की राज्यवार समीक्षा करता रहा है। राज्य योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तथापि अब राष्ट्रीय आयोजना में राज्य स्तर के परिप्रेक्षय की प्रासंगिकता बढ़ रही है। विकास संबंधी मुख्य मुद्दों का राज्यवार विश्लेषण करने और उनका समाधान करने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय विकास पर नीतियों और कार्यक्रमों का वांछित प्रभाव पड़ सके। विशिष्ट राज्यों से संबंधित मामलों पर यद्यपि समय समय पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता रहा है और राज्य सरकारों का योजना आयोग के साथ विचार विमर्श सतत् आधार पर होता है राज्यों के आर्थिक विकास में कुछ ऐसी प्रवृतियां है जो उभरकर सामने आ रही है और जिन पर ध्यान सकेन्द्रित करने की आवश्यकता है। इन मुख्य प्रवृतियों से संबंधित व्यापक विचारष्विमर्श और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए दिशाष्निर्देश राज्यों के लिए हितकर होगें और विकास प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने में सहायक होगें।

1.2 इसी प्रकार पहली बार दसवीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण संकेतकों के लिए प्रबोधन योग्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इन प्रबोधन योग्य लक्ष्यों में से अधिकांश लक्ष्य उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जो राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं और जिन पर राज्य स्तर पर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और इनसे संबंधित आयोजना का समन्वय करने के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रयास किया जाना काघ्य वांछनीय है।

1.3 इस समग्र परिप्रेक्ष्य में, यह खंड निम्नलिखित अध्यायों में बंटा हुआ है :ष

- योजना निवेश और वित्तपोषण
- विकास प्रवृतियां
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
- आयोजना एवं कार्यान्वयन मुद्दे, और
- **सरोकार** और कार्यनीतियां

1.4 राज्य सरकारों के योजना निवेश की शुरूआत देश में विकास आयोजना से आरंभ हुई थी। इन पचास वर्षो की अवधि में यह उम्मीद की जा सकती थी कि सकल घरेलू उत्पाद पर राज्यों के योजना निवेशों का सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि प्रायः इस प्रकार का नतीजा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में हुए अद्यतन परिवर्धनों से निकलता है। परन्तु राज्यों के योजना निवेशों और वित्तपोषण से संबंद्ध कुछ परिपाटियों के कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी।

1.5 योजना निवेशों और वित्तपोषण से संबंधित अध्याय में राज्यों के योजना निवेशों और वित्तपोषण से संबंधित कुछ परिपाटियों तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमताओं को विकसित करने में उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्ष 1974ष2000 की अवधि के दौरान राज्यों के योजना निवेशों के आकार और वित्तपोषण का समग्र रूप से मूल्यांकन किया गया है और राज्यष्वार निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है।

1.6 आयोजना और राज्योन्मुख औद्योगीकरण अपनाने की कार्यनीति के पीछे मंशा यह थी कि देश का अधिक संतुलित विकास हो। ऐसी आशा की जाती थी कि समय के चलते अन्तरष्राज्यीय असमानताएं कम कर दी जाएंगी। योजनाओं और नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया गया कि वे अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए अधिक निवेश प्रदान कर सके। तथापि, राज्यों में सामाजिकष्आर्थिक असमानताएं अब भी विद्यमान हैं।

1.7 विकास प्रवृतियों से संबंधित अध्याय में उपलब्ध और सामान्यतः स्वीकृत विकास संकेतकों के संदर्भ में देश के विभिन्न राज्यों के विकास में तुलनीय प्रवृतियों को प्रकाश में लाया गया है। इस अध्याय को विभिन्न खंडों में विभाजित

किया गया हे जो प्रमुख आर्थिक संकेतकों अर्थात, मानव विकास, आधारिक संरचना और पूंजी प्रवाह संबंधी विशिष्ट विषयों से संबद्ध है।

1.8 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित अध्याय में उत्तरष्पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों और विशिष्ट क्षेत्र विकास से संबंधित उन कार्यक्रमों का समावेश है जो विशेष क्षेत्रों की विलक्षण समस्याओं के समाधान के लिए चल रही है। उत्तरष्पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए की गई विभिन्न पहलशक्तियों और दसवीं योजना के दृष्टिकोण के अतिरिक्त इस अध्याय में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.), पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.), सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) और उड़ीसा के के बी के जिलों से संबंधित दसवीं योजना की कार्यनीतियों की संक्षेप में समीक्षा भी की गई है।

1.9 प्रबंधन के मुद्दे पर इस प्रलेख में व्यापक स्तर पर पहले ही अलग से चर्चा की जा चुकी है। मध्यावधि मूल्यांकन में प्रबंधन से संबंधित अनेक निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया हैं जिनकी राज्य स्तर पर प्रासंगिकता है। इस विश्लेषण के क्रम में इस खंड में आयोजन एंव कार्यान्वयन मुद्दे से संबंधित अध्याय में राज्य स्तर पर प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य पर नजर डाली गई है और इस क्षेत्र में सुधारों के लिए दसवीं योजना के लिए कार्यसूची प्रस्तावित की गई है।

1.10 आयोजन और कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियों में इन वर्षो में धीरे-धीरे जो तकनीकी मुद्दे और चिन्ताएं उभर कर सामने आई है और जिनमें से अधिकांश के कारण राज्य स्तर की आयोजना की हानि और विकृति हो रही है और इसलिए दसवीं योजना में उन पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है इन सबको भी इस अध्याय में शामिल किया गया है।

1.11 अंतिम अध्याय में विकास से संबंधित हमारे तजुरबों से हमने जो सीखा हे उनकी संक्षेप में समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें राज्य आयोजना और विकास में मुख्य चिन्ताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों और दसवीं योजना में राज्यों की संवृद्धि में गति लाने के लिए प्रस्तावित कार्यनीतियों कों शामिल किया गया है।